

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

राज कुमार बृजेंद्र सिंह और अन्य

22 अप्रैल, 2004

[त्रिजेश कुमार और अरुण कुमार, जे.जे.]

हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972:

धारा 20 (3) - वित्तीय आयुक्त कलेक्टर के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अपील वापस लेने के बाद पुनरीक्षण की स्वतः शक्ति का प्रयोग – अभिनिर्धारित, वित्तीय आयुक्त के पास एक उपयुक्त मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ने की शक्ति होगी, भले ही राज्य द्वारा अधीनस्थ अपीलीय प्राधिकारी को वापस लेने से पहले अपील की गई हो – धारा 20 की उपधारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय वित्तीय आयुक्त एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और ऐसी शक्ति के प्रयोग पर इस आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि वह राज्य सरकार की मशीनरी का हिस्सा है या एक राज्य का अधिकारी है - यह एक अलग वैधानिक क्षमता में है जिसके तहत वित्तीय आयुक्त अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और कानून के अनुसार कोई भी आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है जो राज्य सरकार के खिलाफ हो भी सकता है और नहीं भी।

धारा 20(3)- पुनरीक्षण - वित्तीय आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग - परिसीमन - कुछ भूमि को अधिशेष घोषित करने का कलेक्टर का आदेश - राज्य सरकार द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील - इसके 15 वर्ष बाद वित्त आयुक्त ने पुनरीक्षण की स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया - अभिनिर्धारित, , वित्त आयुक्त का आदेश 15 साल के लंबे अंतराल के बाद पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया गया है- समय की अनुचित चूक के बाद शक्ति का प्रयोग और उसकी ओर से इस तरह की विलंबित कार्यवाही धारा 20 की उप-धारा (3) में शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देती है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 130/1999

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 96/1992 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.6.97 से।

साथ में

सी. ए. सं. 131/1999

जे. एस. अत्री, अतिरिक्त महाधिवक्ता, (एच.पी.), (ए.सी.) अपीलार्थियों की ओर से।

बी.एस. बंधिया, प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया :

इस अपील में विवाद हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्लिंग्स एक्ट, 1972 (इसके बाद 'एक्ट' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा से

संबंधित है। उपरोक्त अधिनियम के लागू होने पर, अधिकतम सीमा की कार्यवाही शुरू की गई और जिलाधीश द्वारा 14.1.1976 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल मालिक राजा लक्ष्मण सिंह की 9,000 बीघा भूमि, जिनके उत्तराधिकारी इस अपील में प्रतिवादी हैं, को अधिशेष घोषित कर दिया गया और 1,000 बीघा भूमि छोड़ दी गई जिसे वे परिवार में इकाइयों की संख्या के आधार पर अनुमेय सीमा के भीतर रखने के हकदार पाए गए।

ऐसा लगता है कि राज्य जिलाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित है। इसलिए, उसने आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की। हालाँकि, 20 मार्च, 1976 को राज्य द्वारा अपील वापस ले ली गई थी। जिलाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने के परिणामस्वरूप, जिलाधीश द्वारा पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त की। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय आयुक्त ने अधिनियम की धारा 20(3) के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया है और 7.11.91 के आदेश द्वारा जिलाधीश के दिनांक 14.1.1971 के आदेश को अपास्त कर दिया है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्तीय आयुक्त ने 21.8.1990 को स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की थी। वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों के हाथों में अनुमेय क्षेत्र फिर भी कम किया गया था, इसलिए, उन्होंने वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी। वित्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश की वैधता पर आक्षेप करते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा कई आधार लिए गए थे। कई बिंदुओं में से एक, राज्य द्वारा अपील वापस लेने के बाद स्वतः संज्ञान लेने की वित्तीय आयुक्त की शक्ति का प्रयोग करने से सम्बंधित था दूसरा शक्ति के विलंबित प्रयोग के संबंध में था, अर्थात्,

कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने के लगभग 15 साल बाद। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य द्वारा जिलाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा आयुक्त के समक्ष की गई अपील भी उसी अवधि के आसपास, अर्थात् मार्च, 1976 को वापस ले ली गई।

उच्च न्यायालय ने पाया कि वित्तीय आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों के गुण-दोष में जाना आवश्यक नहीं था और मामले को स्वतः संज्ञान में लेने की वित्तीय आयुक्त की शक्ति से संबंधित प्रश्न से निपटने को प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार द्वारा की गई अपील वापस ले ली गई। जहाँ तक शक्ति के विलंबित प्रयोग के प्रश्न का संबंध है, उसका केवल उल्लेख किया गया है, लेकिन आगे कोई चर्चा नहीं की गई है, सिवाय इस बात के कि अपील दायर करने के लिए निर्धारित सामान्य अवधि 60 दिन है और पुनरीक्षण के लिए यह 90 दिन है।

हम राज्य द्वारा की गई अपील वापस लेने के बाद वित्तीय आयुक्त की स्वतः संज्ञान से आगे बढ़ने की शक्ति के संबंध में पहले आधार पर विचार कर सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह यह है कि वित्तीय आयुक्त उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खुला नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रावधान को केवल पढ़ने पर; अर्थात् धारा 20, दर्शाती है कि राज्य द्वारा की गई अपील वापस लेने के बाद स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 20 से ऐसा कोई पूर्वसर्ग नहीं आता है। अधिनियम की धारा 20 निम्नानुसार है:

“20(1) कलेक्टर के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, आयुक्त के पास अपील कर सकता है। परन्तु, आयुक्त साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) उप-धारा (एल) के तहत दिए गए आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है ताकि इसकी वैधता या औचित्य को चुनौती दी जा सके। आदेश और वित्तीय आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। वित्तीय आयुक्त का आदेश अंतिम होगा.

(3) पूर्वगामी उप-धाराओं में किसी बात के बावजूद, वित्तीय आयुक्त, किसी भी समय, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी भी कार्यवाही या आदेश का रिकॉर्ड मांग सकता है। ऐसी कार्यवाही या आदेश, और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।”

ऊपर उद्धृत धारा 20 की उप-धारा 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि धारा 20 की अन्य उप-धाराओं में किसी भी बात के बावजूद, वित्तीय आयुक्त को अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने और पारित आदेश की वैधता और औचित्य के सम्बन्ध में खुद को संतुष्ट करने की शक्ति होगी। एक बार जब राज्य सरकार ने अपील वापस लेने का निर्णय ले लिया, तो यह प्रस्तुत किया गया कि वित्तीय आयुक्त अपील वापस लेने के राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत कोई अन्य आदेश पारित करने के लिए मामले में कोई अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। हमारे विचार में, यह तर्क भ्रामक है। वित्तीय आयुक्त धारा 20 की उपधारा (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। हम यह भी पाते हैं कि उपधारा 2 के तहत वित्तीय आयुक्त, आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक अपीलीय प्राधिकारी है। धारा 20 की उप-धारा (2) और (3) के तहत उनमें निहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, वित्तीय आयुक्त की शक्ति के प्रयोग पर इस आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि वह राज्य सरकार की मशीनरी का एक हिस्सा है या राज्य का कोई अधिकारी है। यह एक अलग वैधानिक क्षमता में है जिसके तहत वित्तीय आयुक्त अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और कानून के अनुसार कोई भी आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है जो राज्य सरकार के खिलाफ हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए, केवल इस कारण से कि अपील के पक्षों में से एक, राज्य सरकार हो सकती है, ने निचले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील को वापस लेने का फैसला किया, इसे वित्तीय आयुक्त के लिए अधिनियम की उप-धारा 3 के तहत अपनी

शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक बाधा माना जाएगा। इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश का यह हिस्सा सम्पोश्रिय नहीं है।

अब हमारे पास दूसरा प्रश्न रह गया है जो उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, अर्थात्, धारा 20 की उप-धारा (3) के तहत शक्ति के विलंबित प्रयोग। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय आयुक्त ने जिलाधीश के आदेश के 15 साल बाद शक्ति का प्रयोग किया। यह सच है कि उप-धारा 3 में यह प्रावधान है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन इस अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि कोई समय सीमा नहीं होगी या यह अनंत में है। तात्पर्य केवल यह है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। सीमा की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन शक्ति के प्रयोग में अनुचित देरी उन चीजों को पूर्ववत करने की प्रवृत्ति रखती है जो अंतिमता प्राप्त कर चुकी हैं। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उचित समय क्या है जिसके भीतर शक्ति स्वतः संज्ञान कार्यवाही का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस मामले में, क्योंकि अपील वापस ले ली गई थी, लेकिन वित्तीय आयुक्त ने अपनी स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को उठाया था, इसलिए राज्य के लिए यह प्रस्तुत करना खुला हो सकता है कि तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वे उचित समय के भीतर हों, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि जिलाधीश का आदेश जिसमें हस्तक्षेप किया गया है, जनवरी 1976 में पारित किया गया था और राज्य द्वारा की गई अपील को भी मार्च 1976 में कुछ समय के लिए वापस ले लिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऐसे अन्य विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को इंगित करने में सक्षम नहीं थे जिनके कारण यह कहा जा सके कि आदेश में हस्तक्षेप के 15 वर्षों के बाद स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया गया था। हमारे विचार में यह स्थिति होने के कारण, वित्तीय आयुक्त का आदेश 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पारित होने के कारण रद्द हो गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया गया है। इसलिए, यह मानते हुए कि वित्तीय आयुक्त के पास उपयुक्त मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ने की शक्ति होगी, भले ही अधीनस्थ अपीलीय प्राधिकारी से पहले की गई अपील राज्य द्वारा वापस ले ली गई हो। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है। लेकिन वित्तीय आयुक्त का आदेश समय की अनुचित व्यतिक्रम के बाद शक्ति के प्रयोग के दोष से ग्रस्त है और उसकी ओर से इस तरह की विलंबित कार्रवाई धारा 20 की उप-धारा (3) में शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देती है।

ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हम आंशिक रूप से अपील की स्वीकार करते हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय आयुक्त के आदेश को अपास्त किया जाता है और जिलाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल और कायम रखा जाएगा। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सिविल अपील सं. 131/1999

सी. ए. सं. 130/1999 में दिए गए हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए 23 जून, 1997 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को बनाए रखा गया है। राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है।

आर. पी. सी. ए. सं. 130/99 आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

सी. ए. सं. 131/99 खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
